करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

(संग्रह)

जून 2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि की घोषणा 3
- 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश 3
- सम्राट पृथ्वीराज 4
- उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन 4
- राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया 4
- एकेटीयू में एनईपी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये कमेटी का गठन 5
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर 5
- उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री ज़ोन होगा 'काशी विश्वनाथ धाम' 6
- राज्य के पीसीएस अधिकारियों के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल 6
- आगरा कैंट स्टेशन को मिला ग्रीन रेटिंग 7
- उत्तर प्रदेश के 50 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने 7
- उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी इज़रायली तकनीक पर आधारित 150 हाई-टेक नर्सरी 8
- सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है : उच्च न्यायालय 8
- देश में पहली बार बायो स्रोत से खोजी गई नैनो सिलिका 9
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति, 2022 को दी मंज़ूरी 9
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजनगरी में 8 लाख लोग करेंगे योग 10
- निःशक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार 10
- अब ज़मीन दान देने वालों के नाम से अस्पतालों का हो सकेगा नामकरण 10
- 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश ले सकती है महिला 11
- मथुरा के इस्कॉन और प्रेम मंदिर को मिला भोग प्रमाण-पत्र 11
- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप-विभाजन से संबंधित नई नीति को स्वीकृति मिली 12
- उत्तर प्रदेश में जल्द ही ई-रूपी से मिलेगी छात्रवृत्ति 13
- चंबल कटहल महोत्सव 13
- उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी 13
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे कनाडा की कंपनी के हवाले 14
- लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल 14
- घरौनी योजना 15
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये बोर्ड का गठन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार 15
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति के तहत चार निवेश प्रस्तावों को दी मंज़ूरी 15
- अयोध्या में 300 करोड़ रुपए में बनेगा सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट 16

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिये स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह केंद्र सरकार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Members of Parliament Local Area Development Scheme – MPLAD) का ही रूपांतरित स्वरूप है।
- इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढाँचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लिये भी है।
- विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है।
- विधायक केवल दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएलएएलएडी फंड को फरवरी 2020 में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसे कोविड महामारी के कारण 2020-21 में निलंबित कर दिया गया था और 2021-22 में आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था।

15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश देश में 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ 15 करोड़ लोगों को कोविड टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं।
- 19.95 करोड़ की आबादी (जनगणना-2011) वाला उत्तर प्रदेश अब तक राज्य के लोगों को 32.76 करोड़ से अधिक डोज़ प्रदान कर चुका है।
- प्रदेशवासियों को अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी से अब तक लगभग 31.52 लाख बूस्टर डोज दिये जा चुके हैं।
- वहीं राज्य में 15-17 आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 2,45,92,596 से अधिक टीके और 12-14 आयु वर्ग के बच्चों को 1,02,11,117 से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है।

नोट :

सम्राट पृथ्वीराज

चर्चा में क्यों ?

2 जून, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड बायोपिक 'सम्राट पृथ्वीराज' की स्क्रीनिंग में भाग लेने के बाद राज्य में इस फिल्म को कर से छूट देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस फिल्म का निर्देशन डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है तथा पृथ्वीराज की भूमिका अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा निभाई गई है।
- पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान वंश के राजा थे, को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है।
- इन्होंने 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सन् 1178 से 1192 ई. के मध्य उत्तर-भारत में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था तथा इनकी राजधानी अजमेर में स्थित थी।
- वर्ष 2021 में बागपत जनपद के खेकड़ा के निकटवर्ती दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से सटे गाँव काठा के प्राचीन टीले में पुरातात्त्विक स्थल निरीक्षण में पृथ्वीराज चौहान सहित राजा अनंगपाल देव, राजा मदनपाल, राजा चाहड़ा राजदेव के समय के 16 दुर्लभ सिक्के प्राप्त हुए थे।
- तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को पराजित किया था, किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया।
- दिल्ली स्थित किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को ही दिया जाता है

उत्तर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

3 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में 45,529.29 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ गौतमबुद्ध नगर को, 4460.88 करोड़ रुपए की लखनऊ को तथा 2828.86 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ गोरखपुर को प्राप्त हुई।
- इस सेरेमनी में देश-विदेश के कई औद्योगिक दिग्गज शामिल हुए, जैसे- अडानी समूह के गौतम अडानी, आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला।
- इस दौरान औद्योगिक दिग्गजों द्वारा कुछ प्रमुख निवेश घोषणाएँ की गईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
  - अडानी समूह उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का सड़क, परिवहन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और रक्षा क्षेत्र में निवेश करेगा।
  - इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉरिडोर के तहत अडानी समूह कानपुर में 1500 करोड़ रुपए के निवेश से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत आयुध कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
  - हीरानंदानी समूह उत्तर प्रदेश में अगले पाँच वर्षों में डाटा सेंटर कारोबार में प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गौरतलब है कि इस समूह द्वारा ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा डाटा सेंटर इस वर्ष अगस्त तक तैयार हो जाएगा।
  - वहीं फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी एयर लिक्विड मथुरा के कोसी क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए के निवेश से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगी।

राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संत कबीर नगर के मगहर में आने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं, इससे पहले मिसाइल मैन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बतौर राष्ट्रपति यहाँ आए थे।
- उल्लेखनीय है कि स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिये राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

एकेटीयू में एनईपी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये कमेटी का गठन

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2022 को एकेटीयू (डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी) के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) आधारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को तैयार करने के लिये समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये बनाई गई समिति का अध्यक्ष प्रति कुलपति प्रो. मनीष गौड़ को बनाया है। समिति में डीन एकेडमिक और समन्वयक प्रो. नीतेश पुरोहित, डॉ. आर.के. अग्रवाल, डॉ. सारिका श्रीवास्तव तथा डॉ. प्रभाकर गुप्ता भी शामिल हैं।
- कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र ने समिति से पाठ्यक्रमों को चिह्नित कर सत्र 2022-23 से लागू करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर एक महीने में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
- इसके साथ ही संस्थानों के शिक्षकों और विभाग के उत्कृष्ट कार्यों के लिये अवार्ड देने के लिये एक समिति का गठन किया गया है। एकेटीयू अब अपने संबद्ध संस्थानों में रिसर्च और डेवलपमेंट कार्यक्रम को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिये अवार्ड देगा।

खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश को 8वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- मंडाविया ने एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स और ग्रांट्स फेज-II, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फेज-III, स्कूल स्तर पर एक प्रतियोगिता सहित विभिन्न नवीन पहलों की शुरुआत की।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि गुजरात 77.5 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
- बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा 54.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं।
- छोटे राज्यों में गोवा ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी, जबकि मणिपुर और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने शीर्ष तीन रैंक हासिल की।
- गौरतलब है कि राज्यों को खाद्य सुरक्षा के पाँच मानकों- मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व उपभोक्ता सशक्तीकरण पर आँका गया है।
- खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था। नागरिकों के लिये सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेरित करने के लिये भी यह कदम उठाया गया था।

नोट :

उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री ज़ोन होगा 'काशी विश्वनाथ धाम'

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2022 को वाराणसी के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र को कार्बनमुक्त करने के लिये मंदिर प्रशासन ने पहल शुरू की है। यह प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा, जो पूरी तरह से कार्बन व धूलकणों से मुक्त होगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदूषण के स्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने धाम क्षेत्र को कार्बन व प्रदूषणमुक्त करने के लिये एयर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिये सीएसआर फंड के तहत धाम क्षेत्र में 12 जगहों पर एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे।
- गौरतलब है कि मणिकर्णिका घाट पर दहकती चिताओं के कारण काशी विश्वनाथ धाम में पीएम 2.5 और पीएम 10 के साथ ही कार्बन की मात्रा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं निर्माण कार्य के कारण आस-पास के क्षेत्र में पेड़-पौधों में भी कमी आई है।
- मंदिर प्रशासन द्वारा ज़िला प्रशासन व एक कंपनी के सहयोग से ट्रायल के रूप में एयर प्यूरीफायर लगाकर मंदिर के आस-पास की आबोहवा को शुद्ध करने का ट्रायल किया गया था। मंदिर क्षेत्र में लगाई गई इस मशीन में पाँच किमी. तक के क्षेत्र से धूल के कण को सोखने की क्षमता थी।
- काशी विश्वनाथ धाम में हेपा (हाई इफीशिएंसी पार्टिकुलेट एयर) तकनीक पर आधारित एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल काफी वर्षों से हवा को साफ करने के लिये किया जा रहा है।
- हेपा फिल्टर 0.3 माइक्रोन से बड़े 99.97 से अधिक कणों को कैद करने में सक्षम है। मोल्ड और बैक्टीरिया को पकड़ पाने की वजह से यह फिल्टर अधिक स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं।

राज्य के पीसीएस अधिकारियों के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पीसीएस अधिकारियों (PCS Officers) को अपनी चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिये 'स्पैरो-यूपी' पोर्टल का निर्माण किया है। सभी अधिकारियों को लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (NCR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिये थे।
- गौरतलब है कि आईएएस अधिकारियों के लिये अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।
- आईएएस अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। आईएएस अधिकारियों के लिये लागू व्व्यवस्था की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिये भी यह व्यवस्था लागू कर दी है।
- इसके तहत राज्य के सभी पीसीएस अधिकारियों को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्येक अधिकारी को हर साल अप्रैल में पिछले वित्त वर्ष के लिये अपना सेल्फ एप्रेजल भी ऑनलाइन देना होगा। ब्यौरा न देने वाले अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की वार्षिक प्रविष्टि रोकी जा सकती है। इससे इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है।

नोट :

आगरा कैंट स्टेशन को मिला ग्रीन रेटिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आगरा रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन, डीआरएम ऑफिस और रेलवे अस्पताल को हरियाली, कूड़ा प्रबंधन व सफाई के मामले में आईजीबीसी की ओर से ग्रीन रेटिंग दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- आगरा कैंट स्टेशन परिसर को हरा-भरा बनाने के प्रयास पिछले दो साल से चल रहे हैं। स्टेशन के रनिंग रूम के मेस में लोको पायलट और गार्डों के लिये भोजन बायोगैस प्लांट पर बनाया जाता है। यहाँ स्टेशन से एकत्रित कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रेलवे अधिकारियों के यमुना रेस्ट हाउस में भी बायोगैस प्लांट संचालित है। स्टेशन पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है।
- स्टेशन परिसर से लेकर डीआरएम ऑफिस तक सोलर पैनल से 1588.40 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जिससे स्टेशन व अन्य परिसर की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है।
- स्टेशन पर प्रतिदिन एक हज़ार से ज़्यादा रेल नीर समेत अन्य पानी की बोतलों की खपत होती है। इन्हें नष्ट करने के लिये बोतल क्रश मशीनें लगी हुई हैं।
- रेलवे की ऑफिसर्स कॉलोनी से लेकर डीआरएम ऑफिस व अन्य परिसरों को हरियाली से आच्छादित किया गया है। वर्ष 2021-22 में डेढ़ लाख पौधे लगाए गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में अब फल-फूल गए हैं। वर्तमान में केवल स्टेशन परिसर में 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी देखभाल का दायित्व स्टेशन अधीक्षक का है।
- स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर छह पर एसटीपी संचालित है। इसे पानी का ट्रीटमेंट करके पटरियों की धुलाई में उपयोग किया जाता है।
- स्टेशन पर वार्ड के समीप कोच वाशिंग प्लांट से ट्रेनों के कोचों की धुलाई की जाती है। धुलाई के पानी को बर्बाद नहीं होने दिया जाता है। इसे अनेक चैनलों से गुज़ार कर पौधों में दिया जाता है।
- कूड़े के प्रबंधन के लिये रेलवे ने नगर निगम के साथ करार किया है। इसमें कूड़े की छँटाई के बाद इसके निस्तारण का कार्य नगर निगम की टीम करती है।

उत्तर प्रदेश के 50 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने

चर्चा में क्यों ?

11 जून, 2022 को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंगआउट परेड (पीओपी) के बाद उत्तर प्रदेश के 50 युवा भारतीय सेना में अधिकारी बन गए।

प्रमुख बिंदु

- परेड में देश-विदेश के कुल 377 कैडेट्स ने शिरकत की। 150 रेगुलर कोर्स और 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (टीजीसी) से संबंधित कुल 288 जेंटलमैन कैडेट्स (जीसी) पासिंगआउट के बाद भारतीय सेना के गर्वित अधिकारी बन गए।
- आठ मित्र देशों के 89 जेंटलमैन कैडेट्स भी पासआउट होकर अपने-अपने देश की सेनाओं में शामिल हो गए हैं। मित्र देशों में अफगानिस्तान से 43, भूटान से 18, किर्गिस्तान से 1, मालदीव से 3, नेपाल से 1, श्रीलंका से 3, ताजिकिस्तान से 19, तंजानिया से 1 कैडेट पासआउट हुए।
- उत्तर प्रदेश 50 अधिकारियों के साथ जीसी के राज्यवार प्रतिनिधित्व की तालिका में सबसे आगे रहा। पासिंगआउट दल में 33 जीसी के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, जबकि बिहार 28 जीसी के साथ तीसरे स्थान पर तथा हरियाणा 25 जीसी के साथ चौथे स्थान पर रहा।
- गौरतलब है कि भारतीय सैन्य अकादमी से अब तक कुल 34 मित्र देशों के 2724 कैडेट्स पासआउट हो चुके हैं, जबकि भारतीय सैनिक अकादमी अब तक 63 हज़ार 568 सैन्य अधिकारी देश को दे चुकी है।

नोट :

उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी इज़रायली तकनीक पर आधारित 150 हाई-टेक नर्सरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के तहत, इज़रायली तकनीक पर आधारित 150 हाई-टेक नर्सरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इन हाई-टेक नर्सरियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ करेंगी। उद्यान विभाग के अनुमान के अनुसार हाई-टेक नर्सरी की औसत लागत लगभग एक करोड़ रुपए होगी।
- स्कीम के तहत बेर, अनार, कटहल, नींबू, आम, अमरूद, मोरिंगा, ड्रेगन-फ्रूट आदि जैसे फल और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों तथा आसपास के क्षेत्रों के आधार पर मांग के अनुसार कई सब्जियाँ उगाने के लिये प्रत्येक ज़िले में दो हाई-टेक नर्सरी विकसित की जा रही हैं।
- ये 150 हाई-टेक नर्सरियाँ राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों के परिसर में और बागवानी विभाग के अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सके।
- इन नर्सरी को उचित बाड़ लगाने, सिंचाई की सुविधा, हाई-टेक ग्रीन हाउस जैसे बुनियादी ढाँचे से लैस किया जाएगा और सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन)/राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्य समूहों के माध्यम से बनाए रखा जाएगा।
- राज्य सरकार की योजना गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उत्कृष्टता केंद्रों के साथ-साथ हाई-टेक नर्सरी में गुणवत्ता वाले पौधे और बीज उगाने की है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बढ़ती संख्या के लिये पर्याप्त फसल उपलब्ध कराना भी है।
- इन नर्सरी में उत्पादित पौधों को इच्छुक स्थानीय किसानों, क्षेत्रीय स्तर पर किसान उत्पादक संगठनों (FPO), राज्य स्तर पर अन्य निजी नर्सरी और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोपण के लिये बेचा जाएगा।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले पाँच वर्षों के दौरान बागवानी फसलों की खेती के क्षेत्र को 11.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि फलों, सब्जियों और मसालों के प्रसंस्करण के साथ-साथ समग्र उपज बढ़ाई जा सके।
- उल्लेखनीय है कि बस्ती और कन्नौज ज़िलों में क्रमश: फलों और सब्जियों के लिये इंडो-इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध मिल सकें।

सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है : उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सत्र न्यायालय पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान और समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने प्रभाकर पांडेय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
- हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। यदि सत्र न्यायालय को पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य करते समय कोई अनियमितता या क्षेत्राधिकार में त्रुटि मिलती है तो कार्यवाही को रद्द करने की बजाय उसे केवल मजिस्ट्रेट के आदेश में त्रुटि को इंगित करके निर्देश जारी करने की शक्ति है।
- मामले में शिकायतकर्त्ता द्वारा विरोधी पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा- 147, 504, 506, 427, 448, 379 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में जाँच अधिकारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका पर विचार करने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद आरोपी को धारा-379 सीआरपीसी के तहत तलब किया।

नोट :

- इस आदेश को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कन्नौज के समक्ष चुनौती दी गई। सत्र न्यायालय ने जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया। इसलिये याची ने ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कन्नौज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
- हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास चार तरीके होंगे और उनमें से किसी एक को वह आगे की कार्रवाई के लिये अपना सकता है। कोर्ट ने आदेश में उन तरीकों का भी ज़िक्र किया है। साथ ही, कहा कि मामले में सत्र न्यायालय का आदेश पूरी तरह से आरोपी की दलील पर आधारित था, इसलिये मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द करना विधिक तौर पर सही नहीं है।

देश में पहली बार बायो स्रोत से खोजी गई नैनो सिलिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) द्वारा गन्ने की खोई की राख में नैनो सिलिका की खोज की गई है। इसे राख से निकालने की तकनीक भी NSIने विकसित की है, जिसे अब पेटेंट कराया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- NSI के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि नैनो सिलिका पार्टिकल्स की खोज और इसकी तकनीक का विकास सीनियर रिसर्च फेलो डॉ. शालिनी कुमारी ने किया है। इस तकनीक को विकसित करने में दो साल लगे हैं।
- अभी तक विभिन्न मिनरल्स स्रोतों से नैनो सिलिका प्राप्त की जाती थी, लेकिन बायो स्रोत से देश में पहली बार इसे खोजा गया है।
- प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि तकनीक को पेटेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोवा में 28-29 जुलाई को भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संघ के सम्मेलन में भी इस तकनीक को प्रस्तुत किया जाएगा।
- सीनियर रिसर्च फेलो डॉ. शालिनी कुमारी ने इस प्रक्रिया में अम्ल, क्षार और हीट ट्रीटमेंट के चरणों के संबंध में जानकारी दी। नैनो सिलिका तकनीक की जाँच आईआईटी दिल्ली से भी कराई गई। उत्पाद की पुष्टि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे विवर्तन विश्लेषण और फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रा रेड तकनीक से की गई।
- मिनरल्स स्रोत से जो नैनो सिलिका मिल रही है, उसकी कीमत 700 से 1000 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन खोई की राख से मिली नैनो सिलिका की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पड़ेगी।
- गन्ने की खोई का इस्तेमाल चीनी मिल के बॉयलर के ईंधन के रूप में होता है। इससे निकलने वाली राख अभी तक गड्ढ़ा पाटने के ही काम आती थी। इसे प्रदूषण का कारक भी माना जाता है। साथ ही, इसका निस्तारण करने में चीनी मिलों का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन इससे निकलने वाला नैनो सिलिका पार्टिकल्स प्रदूषण सोखने के भी काम आता है।
- गौरतलब है कि देश में चीनी मिलों से 50 लाख टन खोई प्राप्त होती है, जिसे जलाने पर 15 लाख टन राख प्राप्त होती है। इस राख से लगभग तीन लाख टन सिलिका नैनो पार्टिकल प्राप्त किये जा सकते हैं। खोई की एक किलो राख से 20 फीसदी नैनो सिलिका पार्टिकल्स मिलते हैं।
- नैनो सिलिका पार्टिकल्स दवा उद्योग, पेंट और बैटरी उद्योग, लिथियम आयरन बैटरीज, नैनो फर्टिलाइजर आदि में इस्तेमाल होता है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति, 2022 को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति, 2022 को मंज़ूरी दे दी गई। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किये जाएंगे। यह नीति वर्ष 2022-23 के लिये है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत समूह क और ख के अधिकारियों द्वारा जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।
- समूह क और ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग व घ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे।

नोट :

- समूह ख और ग के कार्मिकों के स्थानांतरण मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन व क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश को कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था की गई है।
- बैठक में पुलिस के 40 हज़ार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी गई। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजनगरी में 8 लाख लोग करेंगे योग

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को ताजनगरी आगरा के ज़िलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि इस वर्ष आगरा ज़िले में लगभग 150 स्थानों पर 8 लाख से अधिक लोग योग करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन स्थल, स्मारक, पार्क व अन्य खुले स्थानों पर करीब 8 लाख लोग योग करेंगे। इसके लिये विभागों को लक्ष्य बाँटा गया है।
- विभागों के अलावा एनजीओ, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाएँ भाग लेंगी। समन्वय के लिये मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम व अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
- ज़िलाधिकारी ने बताया कि फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, एत्माद-उद-दौला व अन्य पर्यटन स्थलों पर भव्य आयोजन होगा। विभागों के अलावा एनजीओ, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाएँ भाग लेंगी।
- मुख्य योग शिविर ग्राम पंचायत स्तर से विकास खंड, तहसील व ज़िलास्तर पर होंगे। योग अभ्यास की सामूहिक एवं व्यक्तिगत सूचना आयुष कवच एप पर अपलोड की जाएगी।

नि:शक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की नि:शक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किये हैं।
- आदेश के अनुसार यदि नि:शक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मिलेगा।
- ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिये कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा।

अब ज़मीन दान देने वालों के नाम से अस्पतालों का हो सकेगा नामकरण

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन अस्पताल के लिये दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में अब तक सरकारी अस्पतालों का निर्माण ग्राम समाज अथवा अन्य सरकारी ज़मीन पर किया जाता है। यह ज़मीन आबादी क्षेत्र से काफी दूर होती है। ऐसे में यहाँ चिकित्सक व चिकित्साकर्मी रहने से कतराते हैं। सुनसान इलाके में अस्पताल होने से उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
- स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि आबादी क्षेत्र में अस्पताल रहे तो उसके रख-रखाव व सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण एवं क्रय किये जाने के संबंध में नई नियमावली तैयार की है। इस नियमावली के तहत आबादी क्षेत्र में अब स्वास्थ्य विभाग ज़मीन खरीद कर अस्पताल बनवा सकेगा।
- इसी तरह यह भी विकल्प दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आबादी क्षेत्र की ज़मीन दान में देता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम से किया जा सकेगा। भू-स्वामी अस्पताल के लिये आबादी क्षेत्र की ज़मीन दान करके उतनी ही सरकारी ज़मीन दूर-दराज के क्षेत्र में हासिल भी कर सकता है।
- नई नियमावली में यह भी व्यवस्था की गई है कि नए अस्पताल का निर्माण कराते वक्त यह देखा जाएगा कि संबंधित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में पहले से कोई सरकारी अस्पताल न हो। इसी तरह सामुदायिक एवं ज़िला अस्पताल से भी दूरी के मानक तय किये गए हैं।

2 साल में 2 मातृत्व अवकाश ले सकती है महिला

चर्चा में क्यों ?

16 जून, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया है।

प्रमुख बिंदु

- हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि दो साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। यह लाभ दो साल के अंदर भी दिया जा सकता है। किसी महिला कर्मचारी को दो साल में दो मातृत्व अवकाश का लाभ न देना कानून के खिलाफ है।
- यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला बालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
- याची ने 2020 में 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश लिया था। इसके बाद उसने दूसरे मातृत्व अवकाश के लिये मई, 2022 में BSA को आवेदन किया। BSA ने याची के आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि दो मातृत्व अवकाशों के बीच दो साल का अंतराल ज़रूरी है।
- विदित है कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह यानी साढ़े छह महीने तक मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। यह प्रसव की अनुमानित तारीख से 8 सप्ताह पहले से शुरू हो सकती है। मगर, इस अवकाश के साथ यह शर्त जुड़ी है कि कोई भी महिला अपनी पहली दो गर्भावस्थाओं के लिये यह अवकाश ले सकती है। तीसरा बच्चा होने पर 12 सप्ताह के लिये मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
- कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार याची को मातृत्व अवकाश दिया जाना न्याय के हिसाब से है। फाइनेंशियल हैंडबुक में दिये नियम मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने BSA के आदेश को रद्द करते हुए याची को 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया।

मथुरा के इस्कॉन और प्रेम मंदिर को मिला भोग प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

16 जून, 2022 को एफएसएसएआई भारत सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 'ईट राइट' कार्यक्रम के तहत मथुरा के वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को भोग प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मंदिर में अपने आराध्य भगवान को अर्पित किये जाने वाले भोग तथा प्रसाद की गुणवत्ता के संबंध में मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले भोग को हाइजीन वातावरण एवं रसोईघर में सभी कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पानी की जाँच एवं पेस्ट कंट्रोल (चूहे आदि) की गहन जाँच करने के उपरांत स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा दो बार ऑडिट किया गया।
- ऑडिट रिपोर्ट को एफएसएसएआई भारत सरकार को भेजा गया। परीक्षण के बाद, वृंदावन के इस्कॉन एवं प्रेम मंदिर को भोग प्रमाण-पत्र भारत सरकार ने जारी किया है।
- सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गौरी शंकर ने बताया कि 'ईट राइट' कार्यक्रम के तहत जीएलए विश्वविद्यालय, केडी मेडिकल कॉलेज, संबिद गुरुकुलम, वात्सल्य ग्राम एवं अक्षय पात्र (वृंदावन, मांट) कैंपस को 'ईट राइट कैंपस' के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी भोग प्रमाण-पत्र दिलवाने की प्रक्रिया जारी है।
- सहायक आयुक्त गौरी शंकर ने कहा कि ब्रज के अन्य प्रमुख मंदिर बरसाना के राधा रानी मंदिर, गोवर्धन के गिरिराज जी मंदिर के प्रबंधकों व रिसीवर से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी अपने यहाँ चल रही रसोई की जाँच कराएँ, जिससे उनको भी यह प्रमाण-पत्र मिल सके और प्रसाद लोगों के घर तक पहुँचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप-विभाजन से संबंधित नई नीति को स्वीकृति मिली

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिये औद्योगिक भूखंडों के उप-विभाजन की बहुप्रतीक्षित नई नीति (संशोधित) को मंज़ूरी दे दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने अपने बोर्ड की मंज़ूरी के बाद संशोधित नीति को कार्योत्तर अनुमोदन के लिये सरकार को भेज दिया है। साथ ही राज्य कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गाज़ियाबाद में लगभग 200-300 एकड़ अनुपयोगी पड़े बड़े भूखंड पर छोटे भूखंड बन कर दूसरे उद्यमियों को उपलब्ध हो सकेंगे।
- प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने ऐसे भूखंडों के उप-विभाजन की अनुमति का फैसला किया है, जिन पर कम-से-कम चार वर्ष से औद्योगिक इकाई संचालित है। कुछ मामले में शर्तों के साथ छूट का भी प्रावधान है।
- यदि उप-विभाजित क्षेत्र 25 एकड़ तक है तो इसके लिये गठित समिति की सिफारिश पर प्राधिकरण के सीईओ मंज़ूरी देंगे। यदि उप-विभाजित क्षेत्र 25 एकड़ से अधिक है, तो इसे प्राधिकरण बोर्ड मंज़ूरी देगा।
- प्राधिकरण ने नीति में उपखंड के लिये आवेदन की शर्तें, आंतरिक विकास, स्थानांतरण की प्रक्रिया, विभाजित भूखंड बेचने की शर्तें, रखरखाव कार्य, उप-विभाजित भूखंड पर इकाई के संचालन के लिये समय की अनुमति, उप-प्रभार शुल्क, उप-विभाजन शुल्क, उप-विभाजित भूखंडों के कॉन्फिगरेशन व सेटबैक संबंधी प्रावधान भी किये हैं।
- इस नीति से सक्रिय औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, उपलब्ध अतिरिक्त भूखंड के औद्योगिक उपयोग के साथ उद्यमी परिवारों में तेज उद्यम विस्तार की राह खुलने की उम्मीद है।
- नीति के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं-
  - 4,000 वर्ग मीटर के वे भूखंड उप-विभाजित होंगे, जिन पर 4 वर्ष तक इकाई संचालित रही हो। भूखंड 18 मी. रोड पर होने चाहिये।
  - न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के भूखंड सृजित किये जा सकेंगे।
  - आंतरिक विकास के लिये 18 से 36 महीने का चरणबद्ध समय दिया जाएगा।
  - आवंटित भूखंड का अधिकतम 75% उप-विभाजित किया जा सकेगा।
  - भूखंडों की बिक्री को 2 से 3 वर्ष का समय मिलेगा। इसके बाद समय विस्तार की सुविधा मिलेगी।
  - उप-विभाजन शुल्क प्रचलित दर पर 7.5 से 20% तक होगा। 50% अनुमोदन के समय व 50% पूरा करने पर देना होगा।

नोट :

- उप-विभाजित भूखंड पर एनसीआर में हस्तांतरण शुल्क प्रचलित दर का 15% व एनसीआर से अलग क्षेत्रों में 10% होगा।
- कुछ शर्तों के साथ उप-विभाजित भूखंड के भी उप-विभाजन की सुविधा।
- परिवार-साक्षीदार से जुड़े भूखंड के विभाजन में उप-विभाजन की अर्हता में छूट, कॉमन एरिया सरेंडर न किया जाए, तब तक रखरखाव।

- प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत परिभाषित 'मेगा या अधिक निवेश' के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिये भूखंड के उप-खंड के मामले में भी छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में जल्द ही ई-रूपी से मिलेगी छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम वरुण ने राज्य में ई-रूपी से छात्रवृति मिलने की जानकारी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यमंत्री ने बताया कि ई-रूपी एक तरह का ई-बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले पता चल सकेगा कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं ।
- ई-रूपी से सरकार की ओर से भेजे गए धन को छात्र अपने खाते से न तो निकाल पाएगा और न ही इसका उपयोग किसी अन्य काम में हो सकेगा, सिवाय स्कूल-कॉलेज की फीस का भुगतान करने के।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किये जा रहे ई-रूपी के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी।

चंबल कटहल महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2022 को डाकुओं के आतंक के लिये बदनाम रहे चंबल सहित पाँच नदियों के संगम 'पंचनद' पर 'चंबल कटहल महोत्सव' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह पहला मौका था, जब नदियों के इस संगम के किनारे कटहल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यहाँ न सिर्फ कटहल के बारे में, बल्कि कटहल के उत्पादन के संबंध में भी लोगों ने जानकारी हासिल की।
- चंबल फाउंडेशन चंबल घाटी की सकारात्मक पहचान विश्व के सामने लाने के लिये लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहा है।
- चंबल कटहल फेस्टिवल में कई प्रदेशों से लाए गए कटहलों की प्रदर्शनी लगाई गई। चंबल के बीहड़ में पैदा हुआ, सबसे बड़े आकार के कटहल के साथ ही थाईलैंड के रंगीन कटहल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
- गौरतलब है कि ब्रिटिश काल में चंबल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटहल की खेती होती थी। हत्या जैसे संगीन जुर्म में कटहल के पाँच पेड़ों पर जमानत मिल जाती थी। चंबल घाटी में पका कटहल नहीं खाया जाता है, जबकि केला और अनानास के स्वाद जैसा पका कटहल खाने का देश में खूब चलन है।

उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों से राज्य को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य वेक्टरजनित बीमारियों से बचाने के लिये नियमित स्वच्छता और फॉगिंग अभियान सुनिश्चित करने को कहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जलजनित बीमारियों और अन्य मौसमी अनियमितताओं से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये 1 जुलाई से संचारी रोगों के खिलाफ यह राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जून से नवंबर तक, राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित होते हैं। सरकार द्वारा किये गए सतत् प्रयासों के कारण ही न केवल इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित किया गया है, बल्कि इससे होने वाली मौतों में भी 95 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।
- इसी संदर्भ में अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतते हुए, राज्य सरकार ने पीआईसीयू बेड और प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों से लैस ब्लॉक स्तर पर इंसेफेलाइटिस देखभाल केंद्र स्थापित किये हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही कालाज़ार से मुक्ति के साथ ही मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। ताजा आँकड़ों के अनुसार राज्य में मलेरिया प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक से कम तथा कालाज़ार रोग प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम में देखा गया है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे कनाडा की कंपनी के हवाले

चर्चा में क्यों ?

24 जून, 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर कनाडा की कंपनी को 20 साल तक टोल वसूलने व मरम्मत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रमुख बिंदु

- एनएचएआई ने 20 साल के लिये कनाडा की इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एक्सप्रेस-वे का ठेका दिया है। यह कंपनी 6267 करोड़ रुपए जमा कराएगी और 20 साल तक टोल वसूलने के साथ ही इसकी मरम्मत भी कराएगी। एक्सप्रेस-वे को जल्द ही कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि एक्सप्रेस-वे पर हर साल टोल वसूली के लिये कंपनी का ठेका बदल दिया जाता है और वह कंपनी केवल टोल वसूली तक ही सीमित रहती है। इसकी मरम्मत की ज़िम्मेदारी एनएचएआई की होती है।
- एनएचएआई ने हरियाणा के कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया था। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें ज़मीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक में 10 हज़ार 800 करोड़ रुपए का खर्च आया था।

लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल

चर्चा में क्यों ?

23 जून, 2022 को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन वर्मा ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल (पुलिस सहायता केंद्र) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन वर्मा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों में ऐसे हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिये गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कमिश्नरेट में पहला ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है।
- इस सेल का मकसद ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है।
- इस सेल के शुरू होने से अब ट्रांसजेंडर और महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
- इनकी सुरक्षा के लिये हर थाने में एक सुरक्षा सेल भी बनाया जाएगा। जहाँ पर ट्रांसजेंडरों की शिकायतों का जल्द-से-जल्द निस्तारण किया जाएगा।

नोट :

- अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि यह एक डेडीकेटेड कक्ष है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर और महिलाओं की समस्याओं को गरिमापूर्वक उनके सम्मान के साथ सुना जाएगा। इसके साथ ही शिकायतकर्त्ता की समस्या का निस्तारण होने के बाद उससे इसका फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे इस सेल के कार्यों में सुधार किया जा सकेगा।

घरौनी योजना

चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के गाँवों में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अक्टूबर 2023 तक घरौनी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण-पत्र वितरित करने के लिये आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से पहले ही 34 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
- उन्होंने यह भी बताया कि लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण में तेज़ी लाने के लिये राज्य के 1,10,300 राजस्व गाँवों में ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वेक्षण इस वर्ष अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा।
- घरौनी प्रमाण-पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने तथा इसका विस्तार करने में भी सुविधा प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके सही मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये बोर्ड का गठन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2022 को विश्व बैंक द्वारा 'उत्तर प्रदेश सतत् और समान विकास की ओर' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये एक बोर्ड गठित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके तथा कम या शून्य लागत वाले किसानों द्वारा उत्पादित इनपुट का उपयोग करके विषाक्त मुक्त कृषि को बढ़ावा देना है।
- उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट में बुंदेलखंड क्षेत्र के सात ज़िलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये गंगा नदी के किनारे पाँच किमी. क्षेत्र की पहचान की है।
- प्राकृतिक खेती के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 में एक विशेष अभियान 'गंगा यात्रा' शुरू की थी।
- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के लिये गंगा नदी के किनारे 27 ज़िलों की पहचान की है।
- गौरतलब है कि भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (बीपीकेपी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति के तहत चार निवेश प्रस्तावों को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में डाटा स्टोरेज को स्थानीयकृत करने हेतु 'उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी-2021' के तहत डाटा पार्कों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन के संबंध में चार निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट के इस फैसले से राज्य को डाटा स्टोरेज में 'आत्मनिर्भर' बनने की दिशा में बढ़ावा मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्कों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से राज्य में कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।
- डाटा सेंटरों के महत्त्व को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 'डाटा सेंटर पॉलिसी-2021' तैयार की थी। नीति के तहत विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिये गए हैं।
- हाल ही में राज्य में आयोजित ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए डाटा केंद्रों की स्थापना के लिये थे।
- राज्य में 15,950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से चार डाटा सेंटर पार्कों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें से हीरानंदानी ग्रुप की एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9134.90 करोड़ रुपए, एनटीटी ग्लोबल सेंटर्स और जापान की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1,687 करोड़ रुपए तथा अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा 2,414 करोड़ रुपए और 2713 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएँ शामिल हैं।
- गौरतलब है कि आईटी सेक्टर में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों को 'इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' घोषित किया है। नतीजतन, चीन, ताइवान और कोरिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आगे आई हैं।

अयोध्या में 300 करोड़ रुपए में बनेगा सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर दो किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या की नई तस्वीर बदलने की कवायद में पूरी तरह जुट गई है। इसके लिये श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ-साथ सरकार अयोध्या के विकास के लिये ऐसी कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे शहर का कायाकल्प हो जाए। इस कड़ी में राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद सरयू किनारे अयोध्या की सरयू रिवर फ्रंट सबसे बड़ी परियोजना है।
- इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
- इसमें सबसे पहले बीच के जो कच्चे घाट थे, उन्हें 39 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा रहा है।
- इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ के समय परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही, पर्यटकों को नई सौगात मिलेगी।
- सरयू के किनारे नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट, पापमोचन घाट, ऋणमोचन घाट, अहिल्याबाई घाट, जटायु घाट, जानकी घाट और नया घाट जैसे कई प्रसिद्ध घाट हैं।
- गौरतलब है कि 232 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सबसे लंबे घाट का प्रस्ताव दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड ने सरकार को भेजा था।

नोट :